नवभारत
संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

## मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक दस्तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान यात्रा को महज कूटनीतिक यात्राओं की श्रृंखला के रूप में देखना भूल होगी. बदलती वैश्विक व्यवस्था में मध्य एशिया भारत की विदेश नीति का ऐसा मोर्चा बनकर उभर रहा है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, सामरिक हित और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई एक-दूसरे से जुड़ते हैं. उज्बेकिस्तान के साथ संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाना इसी बदलती रणनीति का स्पष्ट संकेत है.

यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति को लेकर बनी सहमति है. भारत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए परमाणु ईंधन की सुनिश्चित आपूर्ति अनिवार्य है. उज्बेकिस्तान के साथ संभावित समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ उसकी परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को भी आधार देगा. ऊर्जा के वैश्विक बाजार में अस्थिरता के मौजूदा दौर में ऐसे भरोसेमंद स्रोतों का महत्व और बढ़ जाता है. दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को पांच अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है. आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पीछे छिपी संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत को मध्य एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ नई साझेदारी का अवसर देता है.

भारत की डिजिटल क्षमता और तकनीकी कौशल तथा मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधन परस्पर लाभ का आधार बन सकते हैं. इस पूरी कवायद का एक बड़ा रणनीतिक पक्ष चीन भी है. चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी आर्थिक मौजूदगी काफी मजबूत की है. भारत को चीन की नकल करने के बजाय अपनी विशिष्ट ताकत के आधार पर विकल्प प्रस्तुत करना होगा. भारत की विश्वसनीयता, लोकतांत्रिक छवि, डिजिटल तकनीक, दवा उद्योग और मानव संसाधन उसे इस क्षेत्र में अलग पहचान दे सकते हैं. यही वजह है कि मध्य एशिया में भारत की सक्रियता केवल व्यापारिक विस्तार नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का प्रयास भी है.

किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन इस रणनीति को व्यापक क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है. आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का रुख केवल राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए. अफगानिस्तान की अस्थिरता और उससे जुड़े आतंकी नेटवर्क की चुनौती मध्य एशिया से लेकर भारत तक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. एससीओ जैसे मंच पर भारत को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक और प्रभावी तंत्र बनाने की दिशा में दबाव बढ़ाना होगा.

हालांकि चुनौती यह है कि कूटनीतिक गर्मजोशी को जमीन पर आर्थिक परिणामों में कैसे बदला जाए. मध्य एशिया तक सीधी और सुगम पहुंच भारत की सबसे बड़ी कमजोरियों में रही है. चाबहार बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे और अन्य संपर्क परियोजनाओं को गति दिए बिना व्यापार का पांच अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा. प्रधानमंत्री की मध्य एशिया यात्रा का असली महत्व यही है कि भारत अब इस क्षेत्र को दूर का पड़ोसी मानकर नहीं चल रहा. ऊर्जा से लेकर सुरक्षा और तकनीक से लेकर व्यापार तक, मध्य एशिया भारत के लिए भविष्य का रणनीतिक गलियारा है. अब परीक्षा कूटनीतिक घोषणाओं की नहीं, उन्हें ठोस साझेदारी में बदलने की है. यदि भारत इसमें सफल रहा तो मध्य एशिया में उसकी मौजूदगी केवल चीन के प्रभाव का संतुलन नहीं बनेगी, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को भी नई ताकत देगी.

# सोनिया गांधी की किताब पर हंगामा है क्यों बरपा?

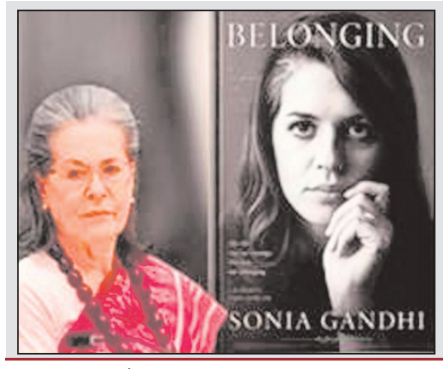


### क्या सरकार तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहती है?

*सोनिया गांधी ने यह भी बताया है कि वह तो प्राइवेट जीवन व्यतीत करना चाहती थीं, लेकिन सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वह किन कारणों से मजबूर हुई. सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं. उन्होंने अपने इस कार्यकाल की भी पुस्तक में चर्चा की है और यह भी विस्तार से बताया है कि 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से क्यों इनकार कर दिया था ?*

**कांग्रेस** सांसद सोनिया गांधी की मेमॉयर (संस्मरण) 'बिलांगिंग' पर विवाद खड़ा हो गया है. भारत में इसके प्रकाशन को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) ने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि उसने पुस्तक के जिन अंशों को संपादित करने का सुझाव दिया था, उन्हें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने मानने से इनकार कर दिया था. इसे 'लोकतंत्र की हत्या' कहते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है, 'पेंगुइन इंडिया पर दबाव डाला गया था कि पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस व मोदी शासन के दौरान चीन ने जो भारतीय भूमि पर कब्जा किया है, उससे संबंधित अंशों को निकाल दिया जाए.' लेकिन पेंगुइन ने सावधानीपूर्वक गठित अपने वक्तव्य में कहा है, पीआरएचआई भारत में 'बिलांगिंग' का प्रकाशक नहीं है.

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी प्रकाशक अल्फ्रेड ए नोफ जो सोनिया गांधी की पुस्तक की 1,00,000 कॉपियां प्रकाशित कर रहा है, वह भी पेंगुइन रैंडम हाउस का ही डिवीजन है. 'बिलांगिंग: ए जर्नी इन लव' के कवर पर युवा सोनिया गांधी की तस्वीर है और इस पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 नवंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा. विवाद के बाद भारतीय प्रकाशकों में इस पुस्तक को प्रकाशित करने की होड़ लग गई है. अनुमान यह है कि भारत में इसे हार्पर कॉलिंस प्रकाशित करेगा. बहरहाल, सवाल यह है कि अगर पेंगुइन का ही डिवीजन नोफ बिना किसी बदलाव के पुस्तक को उसके मूल रूप में प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गया, तो फिर पेंगुइन भारतीय संस्करण में परिवर्तन की मांग क्यों कर रहा था? क्या कहीं से कोई दबाव था कि एक पुस्तक दुनियाभर में तो छप सकती है, लेकिन भारतीय पाठक उसे संशोधित रूप में पढ़ें? क्यों? वैसे भी पुस्तक में लेखक के अपने विचार व अनुभव होते हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, उन्हें कोई प्रकाशक 'फैक्ट चेक' क्यों करना चाहता है? क्या कोई ऐसा कड़वा सच है, जिसे भारतीय जनता से छुपाने का प्रयास है?

गहलोत का आरोप है कि 'मोदी सरकार प्रकाशकों पर दबाव डालकर तथ्यों को भी तोड़ना-मरोड़ना चाहती है'. ऐसा प्रतीत होता है कि पेंगुइन असहज करने वाले तथ्यों या बातों को प्रकाशित करके किसी भी सूरत में सरकार को नाराज नहीं करना चाहता. ध्यान रहे कि पेंगुइन ने इस साल के शुरू में मुजफ्फरनगर दंगों पर कार्टूनिस्ट जो सैको की पुस्तक 'द वन्स एंड फ्यूचर रायट' के वितरण को भारत में रोक दिया था. ऐसा लग रहा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की

संस्मरण पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के कंटेंट पर फरवरी 2026 में संसद में हुए जबरदस्त विवाद के बाद पेंगुइन फूंक-फूंककर कदम रख रहा है. 2020 के लद्दाख व गलवान सीमा विवाद से संबंधित इस पुस्तक के अंश पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे और पुस्तक की 'कॉपियां' भी ऑनलाइन उपलब्ध थीं, जबकि सरकार का कहना था कि जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका हवाला संसद में कैसे दिया जा सकता था? पुस्तकों को प्रकाशन, वितरण से रोकना या प्रकाशक द्वारा लेखक पर पांडुलिपि में रद्दोबदल का दबाव डालना संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन है. सोनिया गांधी की 544 पेजों की किताब इटली के छोटे से गांव में उनकी परवरिश, कैंब्रिज में शिक्षा, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात, रोमांस व शादी आदि को बयान करती है. यह उनकी सबसे अधिक व्यक्तिगत किताब है, जो उनके दिल से निकली हुई प्रतीत होती है. इसमें उन्होंने अपनी व्यक्तिगत त्रासदियों की भी समीक्षा की है, विशेषकर सास इंदिरा गांधी व पति राजीव गांधी की हत्याओं की.

**- शाहिद ए चौधरी**

# बनावटी मामलों पर अदालत सख्त

*धनवान मुकदमेबाज अपने वकीलों पर भरपूर पैसा खर्च कर सकते हैं, ताकि कानूनी लड़ाई अनेक वर्षों तक चलती रहे, लेकिन गरीब व्यक्ति कहां जाए ! अंडरट्रायल गरीब व कम पढ़े-लिखे कैदी का तो मामला ही लटकता रहता है.*

**देश** की अदालतों में 5.6 करोड़ से भी अधिक मामले बकाया हैं. 11 लाख मुकदमे तो 20 वर्ष से भी अधिक समय से पेंडिंग हैं. इसकी वजह न्यायाधीशों की कमी, न्यायपालिका का अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सहयोगी स्टाफ की कमी, प्रक्रिया की जटिलता, मामलों का कमजोर प्रबंधन, जांच व साक्ष्य जुटाने में विलंब आदि हैं. इसलिए साधनहीन गरीब न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं. उन्हें अदालत बार-बार जाने से अपने रोजगार का नुकसान होता है, पेशी बढ़ने से कानूनी खर्च बढ़ता है और अनिश्चितता घेर लेती है. इसके विपरीत संपन्न मुकदमेबाज अपने विवाद को अदालत में लंबा खींचते हैं और अपना हिसाब बराबर करने या नाक ऊंची रखने के लिए भरपूर पैसा खर्च करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 11 वर्षों से चले आ रहे ऐसे ही एक मामले को बनावटी विवाद या लग्जरी लिटिगेशन बताते हुए दोनों पक्षों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि अदालत से दोनों पक्षों ने तथ्य छुपाए और नई बातें जोड़कर मामला बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. बेंच को इस केस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक-एक तथ्य की छानबीन करनी पड़ी. ऐसे बनावटी विवादों की वजह से सामान्य न्यायदान में देरी होती है. धनवान मुकदमेबाज अपने वकीलों पर भरपूर पैसा खर्च कर सकते हैं, ताकि कानूनी लड़ाई अनेक वर्षों तक चलती रहे, लेकिन गरीब व्यक्ति कहां जाए! अंडरट्रायल गरीब व कम पढ़े-लिखे कैदी का तो मामला ही लटकता रहता है. विधि आयोग और संसदीय समितियों ने न्यायपालिका में जजों की कमी व प्रक्रिया की अक्षमता का मुद्दा बार-बार उठाया है. यह समस्या तभी हल हो सकती है, जब खाली पदों पर नियुक्ति हो, फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं तथा मध्यस्थता से विवाद हल करने को प्रोत्साहित किया जाए.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

मालवा- निमाड़ की डायरी

# सिंघार, डोडियार को मनाने में विफल

संजय व्यास

**इन** दिनों कांग्रेस विधायक व विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासियों के सर्वसम्मत नेता बनने की मशक्कत में लगे हैं. अंचल से ही झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. दोनों के बीच इसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है. उमंग सिंघार ने सामानांतर संस्था मप्र आदिवासी विकास परिषद बना रखी है और वे उसके अध्यक्ष हैं. सिंघार ने कुछ वर्षों में अपनी सशक्त परिषद टीम के साथ भूरिया परिवार का स्थापित झाबुआ क्षेत्र छोडक़र अंचल भर में वर्चस्व कायम किया है और अपना खेमा बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं. वे क्षेत्र में आदिवासियों के मध्य प्रभावशाली जयस नेताओं को जोडऩे में कामयाब रहे हैं.

इसी कड़ी में पिछले दिनों सिंघार जयस नेता हीरालाल अलावा की तर्ज पर भारत आदिवासी पार्टी विधायक कमलेश्वर डोडियार पर डोरे डालने सैलाना पहुंचे थे. कहने को जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के हक की लड़ाई में सहयोग की चर्चा मुद्दा था, मगर सिंघार की चाहत उन्हें पार्टी में लाने की रही. सिंघार और डोडियार की वार्ता सिंघार के एजेंडे पर सिरा नहीं पा सकी. डोडियार को आदिवासी परिषद या कांग्रेस में जाने पर कोई फायदा नजर नहीं आया, जबकि भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के एकमात्र विधायक रहते उनके सामने संभावनाओं के कई द्वार खुले नजर आ रहे हैं. सो उन्होंने बाप में बने रहने का अपना स्टेंड जता कर सिंघार को टरका दिया.

### राष्ट्रीय छवि बनाने को प्रयासरत कमलेश्वर

भारत आदिवासी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने को प्रयासरत सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी स्वीकार की है. डोडियार को आशा है कि अधिवेशन में पार्टी उन्हें राष्ट्र स्तर पर कोई संगठनात्मक जिम्मेवारी जरूर सौंपेगी. वे भारत आदिवासी पार्टी के 9-10 सितम्बर रतलाम में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन की जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं. अधिवेशन में मध्यप्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कई राज्यों के पार्टी पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा गया है. अधिवेशन में पार्टी की पिछली गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ आगामी लक्ष्यों और और कार्य योजनाओं पर सामूहिक रूप से ठोस निर्णय लिए जाएंगे.

पार्टी के विस्तार के साथ आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. प्रदेश के एक मात्र भारत आदिवासी पार्टी के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के अनुसार अधिवेशन में आदिवासी समाज के अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों की प्रभावी रक्षा के लिए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने के रणनीति बनेगी ताकि देश भर भर आदिवासियों दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो सके.

## उपेक्षा पर कार्यकर्ताओं में उबाल

हाल ही में घोषित धार जिला कांग्रेस कार्यकारिणी में समर्पित कार्यकर्ताओं को स्थान न मिलने से उबाल है. उपेक्षा के खिलाफ दसई ब्लॉक के कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की है. उन्होंने इस लापरवाही के लिए जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं व क्षेत्रीय विधायक को जिम्मेवार ठहराया है. वर्षों से संगठन के हर कार्य में अग्रणी कार्यकर्ता कार्यकारिणी में लिए जाने की बाट जोह रहे थे, शामिल अन्य लोग कर लिए गए. उनका आरोप है कि कार्यकारिणी में पार्टी के लिए जी-जान खपाते आ रहे कार्यकर्ताओं की बजाए अन्य दलों से आए लोगों को तवज्जो मिल गई. इन नाराज कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी श्रीमती उषा नायडू को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करके अपनी नाराजगी जाहिर कर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं व विधायक के प्रति कड़ा विरोध जाहिर किया है.

निशानेबाज

# पहले अपना बीमा करवाना, बाद में तीर्थयात्रा पर जाना

**प**ड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, तीर्थयात्रा के बिना जीवन किस काम का! सोचते हैं जब तक हाथ-पैर चलते हैं, मजे से तीर्थयात्रा कर आते हैं. देश की चारों दिशाओं में चार धाम हैं, जैसे कि द्वारका, जगन्नाथपुरी, बदरीनाथ और रामेश्वरम! उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का मतलब है- जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ जाना. पंडित लोग कहते हैं- बदरीनाथ में भगवान विष्णु का सिर है और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके चरण. इसके अलावा देश में 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं. अब हम अपना ग्रुप बनाकर तीर्थाटन पर निकल जाते हैं.'

हमने कहा, 'इसके पहले अपनी वसीयत लिखवाइए ताकि परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद न हो. मोटी रकम का बीमा करवा लीजिए. तीर्थयात्रा के दौरान अगर आपकी आत्मा सीधे परमात्मा से मिल गई तो आपके परिवार को काफी दौलत मिल जाएगी.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, हम भले-चंगे हैं, एकदम टनाटन! आपने जो बताया वो सारे काम तीर्थयात्रा से लौटने

के बाद भी कर सकते हैं. इतनी जल्दबाजी किस काम की?'

हमने कहा, 'जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. वंदे भारत ट्रेन से जाएंगे तो शरारती लोग उस पर पथराव ह्रश्व बीमा करते हैं. शीशा तोड़कर पत्थर आपके सिर पर लगा तो बचना मुश्किल है. विमान यात्रा करोगे तो एयर टर्बुलेंस में फंसकर विमान गोता खाएगा. अजीत पवार जैसे बड़े नेता के लिए विमान यात्रा जानलेवा रही. हिमालय के पहाड़ी सड़कों पर कोई बस सीधे सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर सकती है. लैंडस्लाइड हुई तो भी बच पाना कठिन है. केदारनाथ में 2013 में और अभी नेपाल में कितनी भयंकर त्रासदी हुई, आपको पता ही है. सीधा ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है. यदि कुंभ मेले में जाने की सोचेंगे अथवा किसी प्रसिद्ध मंदिर में त्योहार के मौके पर जाएंगे तो भगदड़ में कुचले जाएंगे. हम तीर्थयात्रा के लिए मना नहीं कर रहे हैं. आपको इंश्योरेंस कराने की सलाह दे रहे हैं.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, आपने हमें इतना डरा दिया कि अब कहीं जाने की बजाय यहीं भगवान का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा! हर प्राणी के हृदय में भगवान निवास करते हैं. कबीर ने कहा था- मोहे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा में, ना काशी में और ना कैलाश में !'

## शब्द-सागर 12366

- डॉ. सागर खादीवाला

**बाएं से दाएं**

1.जगमगाना, प्रकाशित होना 3. भोजन करना 6. गोद लिया हुआ लड़का, दत्तक 8. मन बहलाने या प्रसन्न करने वाला 10. समस्त शब्दों में प्रयुक्त होने वाला 'नाक' का संक्षिप्त रूप 11. कीच, कीचड़ 12. जानकारी, खोज, अनुसंधान 14. पलक का गिरना 17. पति की बहन 18. मेघ, घन 19. मिट्टी का बड़ा घड़ा 20. नाटा मनुष्य, बहुत ठिगना आदमी 21. बहुत ऊंचा या गोलाकार स्तंभअथवा इमारत, लाट 22. जमीन खोदकर बनाई हुई पतली तंग जगह जिसमें जीव-जंतु रहते हैं

**ऊपर से नीचे**

1. राजनैतिक सिद्धांत जिसमें यह माना जाता है कि सब प्रकार के दोष तुरंत और चाहे जैसे हों उनका निराकरण होना चाहिए (एक्स्ट्रीमिज्म) सं. 2. अप्रसन्न 3. घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी, काठी 4. यंत्र, कल 5. सिक्ख संप्रदाय के संस्थापक महात्मा 7. घबराहट, हिचक 9. बहुत पतला सिरा, सूक्ष्म अग्रभाग 13. कपड़े की बुनावट में लंबाई और चौड़ाई के बल बुने हुए सूत 14. झन-झन का शब्द 15. ओहदा, पांव 16. बारीक सूत का बना बारीक कपड़ा 17. इनकार करना, नाट्य करना 19. मसालों आदि से सुरक्षित रखा गया शव 20. आम की मंजरी, मौर

**Solution 12365**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स | लो | ना | | सं | पा | द | न |
| हा | | भि | ज | वा | ना | | म |
| नु | क्स | | न | र | | ना | क |
| भू | | ब | क | ना | | रा | ह |
| ति | त | ली | | | ब | ज | रा |
| | र | | ति | रं | गा | | म |
| इ | क | का | ल | | व | श | |
| क | श | | वा | | त | र | ह |

## ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

### आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में व्यापारिक कार्यों में अधिक परिश्रम से आंशिक सफलता के योग है. व्यय और संतान की चिन्ता से मन अशांत रहेगा. वाणी में कठोरता तथा प्रियजनों के प्रति उदासीनता रहेगी. निर्णय सोच विचार कर लें. वर्ष के अन्त में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भाईयों का सहयोग बना रहेगा. नवीन कार्यों में रूचि रहेगी. व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. भाईयों का सहयोग मिलेगा. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को व्यवसायिक कार्यों में परिश्रम अधिक करना होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को सत्ता पक्ष में रूचि रहेगी. सिंह राशि के व्यक्तियों को संतान की चिन्ता रहेगी, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को राज्य सम्मान की प्राप्ति होगी. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को निर्णय सोच विचार कर लेना हितकर रहेगा. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर कार्य करना हितकर रहेगा.

### आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक बुद्धिमान चंचल और मिलनसार होगा. क्रोधी निडर और निर्णय के मामले में निपुण होगा. प्रत्येक कार्य अपने तरीके से पूर्ण करने वाला निष्ठा एवं लगन से कार्य करेगा. माता पिता का आदर करने वाला होगा. देश विदेश की यात्रा करेगा.

### उदयकालीन ग्रह चाल

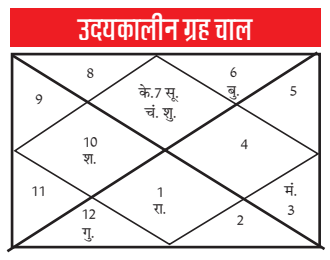


### पंचांग

रा.मि. 10 संवत् 2083 भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी भौमवासरे प्रात: 7/15 तदुपरि पंचमीं तिथौ रातअंत 5/39, अश्विनी नक्षत्रे रात 3/17, वृद्धि योगे रात 1/10, बालव करणे सू.उ. 5/44, सू.अ. 6/16, चन्द्रचार मेष, शु.रा. 1,3,4,7,8,11 अ.रा. 2,5,6,9,10,12 शुभांक- 3,5,9.

### व्यापार भविष्य

भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी/पंचमीं को अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से सोना, चांदी, तांबा, धानु, नीलम, मोती, पुखराज, उड़द, घी, अलसी, तिल, गुड़, खांड़, कपास के भाव में वृद्धि होगी. वायदा विचार आज 11 बजकर 1 मिनिट से 18 मिनिट से 25 मिनिट के रूख पर व्यापार लाभकारी रहेगा. भाग्यांक 5736 है.

**मेष**- श्रम प्रयास से अभीष्ट कार्यों की पूर्ति होगी. शुभ संदेश मिलेगा. लाभदायक महत्वपूर्ण कार्य बनेगा. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. साहस रहेगा.

**वृषभ**- मतभेद दूर होने से रिश्ते मजबूत होंगे. आकस्मिक धन लाभ होगा. कार्यों की अधिकता रहेगी. विशिष्टजनों से संपर्क लाभदायक रहेगा.

**मिथुन**- इच्छित सफलता के लिये कार्य योजना में बदलाव संभव. आत्म विश्वास एवं मनोबल बना रहेगा. पारिवारिक यात्रा सुखद एवं आनन्ददायक रहेगी.

**कर्क**- आलस्य उदासीनता और कामकाज के प्रति अरूचि रहेगी. दैनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होगी. प्रियजनों से विवाद हो सकता है, वैवाहिक चर्चा होगी.

**सिंह**- मदद मिलने से कामकाज की राह आसान होगी. व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी. मांगलिक कार्यों में खर्च होगा. प्रवास आदि का योग है.

**कन्या**- व्यापारिक कार्यों में लगन, उत्साह बना रहेगा. प्रयास सफल होगा. मन में प्रसन्नता रहेगी. मनोनुकूल कार्य बनेगा. परिश्रम सार्थक होगा.

**तुला**- मानसिक अस्थिता रहेगी. लेखन अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न होगी. निजी पुरूषार्थ बना रहेगा. अनावश्यक विवाद को टालना हितकर रहेगा.

**वृश्चिक**- भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी. संपत्ति विवाद में सफलतापूर्वक कार्य बनेगा. राजकीय कार्यों में यश एवं कीर्ति प्राप्त होगी.

**धनु**- रूके कार्य बनने का योग है. आत्म विश्वास और मनोबल बना रहेगा. बना काम बिगड़ सकता है. आर्थिक योजनाओं की रूपरेखा बनेगी.

**मकर**- पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा. सुख सम्मान एवं यश कीर्ति की प्राप्ति होगी. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के आसार हैं.

**कुम्भ**- मानसिक सुख एवं प्रसन्नता रहेगी. मनोरंजन, भ्रमण, आमोद प्रमोद, के अवसर आयेंगे. लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी. धार्मिक कार्यों में खर्च होगा.

**मीन**- जमीन जायजाद संबंधी कामकाज बनेगा. व्यवसायिक समस्याओं का निदान होगा. मन की बात मित्रों से कह दें, इससे तनाव कम होगा.

## SUDOKU 7498

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | | | | 2 | 6 | | 3 |
| | | | 4 | | | | | |
| 1 | 3 | 5 | | 8 | | | | |
| | 2 | | | 1 | | | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| 6 | 7 | | | 9 | | | 2 | |
| | | | | 6 | | 5 | 9 | 2 |
| | | | | | 3 | | | |
| 2 | | 8 | 5 | | | | 6 | 1 |

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. • पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. • पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7497

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 |
| 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 |

योगेश कुमार गोयल <द्वद्गस्रद्बड्डुष्ड्डुह्लद्गद्दह्मश्वह्लश्चञ्चद्दद्बड्डुद्बद्य.ष्श्वद्ब>
ह्लह्लड्डुष्द्धद्बद्गठ्ठह्लह्य
1:04 ?क्करू(3 द्धश्वह्लह्लह्य ड्डुद्दश)
ह्लश ड्ढष्: द्वद्ग

संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, भारत की सनातन आत्मा की अभिव्यक्ति है। इस वर्ष 28 अगस्त को मनाया जा रहा 'विश्व संस्कृत दिवस' न केवल संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का उत्सव है बल्कि इसके पुनरुद्धार का संकल्प भी है। वैदिक ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य की यह जननी भाषा आज फिर से तकनीक, शिक्षा और वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रही है। भारत के मत्तूर, होसाहल्ली, झिरी, सासन, गनोड़ा जैसे गांवों से लेकर जर्मनी व अमेरिका तक संस्कृत पुन: जीवंत हो रही है।

विश्व संस्कृत दिवस पर अपना विशेष लेख ''देववाणी से डिजिटल युग तक: विलुप्ति के कगार से वैश्विक मंच की ओर संस्कृत: शास्त्र, विज्ञान और संस्कृति का संगम है संस्कृत'' प्रकाशनार्थ संलग्न कर रहा हूं। यह लेख प्रकाशित किए जाने पर आभारी रहूंगा।
सादर,
योगेश कुमार गोयल

विश्व संस्कृत दिवस (28 अगस्त) पर विशेष
देववाणी से डिजिटल युग तक: विलुप्ति के कगार से वैश्विक मंच की ओर संस्कृत
शास्त्र, विज्ञान और संस्कृति का संगम है संस्कृत
– योगेश कुमार गोयल
प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को 'विश्व संस्कृत दिवस' मनाया जाता है। इस वर्ष 28 अगस्त को मनाया जा रहा यह दिवस भारत की उस सनातन संस्कृति, ज्ञान, विचार और वैदिक परंपरा का स्मरण और सम्मान है, जो सदियों से इस राष्ट्र की आत्मा में संचित है। संस्कृत को 'देववाणी' या 'देवभाषा' भी कहा जाता है, यह भाषा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही बल्कि समूची भारतीय ज्ञान परंपरा की मूलधारा रही है। वैदिक ऋचाओं से लेकर दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, संगीत, धर्म, साहित्य और नीति तक को संस्कृत अपनी गोद में पालती रही है। संस्कृत दिवस का उद्देश्य संस्कृत भाषा को फिर से जीवंत करने, संरक्षण देने और वैश्विक मंचों पर इसके महत्व को रेखांकित करने का सामूहिक प्रयास भी है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1969 में हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा को 'संस्कृत दिवस' के रूप में मनाए जाने की परंपरा आरंभ की थी। यह वही दिन है, जब प्राचीन भारत में गुरुकुलों में नए शिक्षण सत्र का आरंभ होता था और शास्त्रों के पठन-पाठन की विधिवत शुरुआत होती थी। इस दिन को 'ऋषि पर्व' भी कहा जाता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऋषियों को ज्ञान का आदि स्रोत और गुरु माना गया है। संस्कृत शब्द 'संस्कृतम्' का शाब्दिक अर्थ है 'संस्कारित', 'सज्जित' या 'परिष्कृत'। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक, व्याकरण-संपन्न, संगठित और वैचारिक रूप से समृद्ध है। इसकी संरचना में तर्क, स्पष्टता और शुद्धता इतनी सहज है कि यह उच्च विचारों और जटिल अवधारणाओं को भी सरलतम रूप में अभिव्यक्त कर सकती है।

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम ज्ञात भाषाओं में से एक है, जिसकी जड़ें 3500-4000 वर्ष पूर्व तक जाती हैं। संस्कृत व्याकरण का अद्भुत ग्रंथ 'अष्टाध्यायी', जिसे पाणिनि ने रचा, आज भी भाषा विज्ञानियों को चकित करता है। दरअसल इसकी संरचना इतनी परिष्कृत है कि इसे दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में गिना जाता है। वर्ष 1985 में अमेरिकी वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स ने अपने शोध में यह निष्कर्ष निकाला कि संस्कृत भाषा का व्याकरणीय ढांचा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सर्वोत्तम अनुकूलता रखता है। उनके उस अध्ययन ने पश्चिमी दुनिया को भी संस्कृत की ओर आकृष्ट किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक विशिष्ट भाषा माना जाने लगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को मान्यता प्राप्त है और उत्तराखंड ने इसे अपनी द्वितीय राजभाषा घोषित किया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान', 'संस्कृत भारती', 'संस्कृत संवर्धन परिषद' जैसे संगठन संस्कृत के प्रचार-प्रसार में सतत प्रयत्नशील हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पोर्टल और एनडीएलआई (भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संस्कृत ग्रंथों की सहज उपलब्धता ने शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं।

संस्कृत केवल शास्त्रों की भाषा नहीं रही बल्कि आज भी देश के कई गांवों में जीवंत है। कर्नाटक के शिमोगा जिले का मत्तूर गांव इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां 9500 से अधिक लोगों की मातृभाषा संस्कृत है। यहां बच्चे संस्कृत में शिक्षा लेते हैं, घरों में संस्कृत में संवाद होता है और समाज का समूचा व्यवहार इसी भाषा में संचालित होता है। वर्ष 1981 में संस्कृत भारती के प्रयास से यहां 'संस्कृत संभाषण आंदोलन' की शुरुआत हुई थी, जिसके फलस्वरूप यह गांव केवल दो वर्षों में ही 'संस्कृत ग्राम' के रूप में देशभर में प्रसिद्ध हो गया। 'शारदा शाला' नामक विद्यालय में बच्चों को संस्कृत के साथ वेद, योग और भारतीय दर्शन की शिक्षा दी जाती है। विशेष बात यह है कि यह गांव जातिवाद और सामाजिक भेदभाव से मुक्त है तथा यहां के निवासी आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी और कन्नड़ में भी दक्ष हैं।

मत्तूर के जुड़वां गांव होसाहल्ली की भी यही विशेषता है, जहां के लोग संस्कृत को न केवल संवाद की भाषा बल्कि जीवन पद्धति मानते हैं। लगभग 5000 लोगों को संस्कृत की शिक्षा देने वाले होसाहल्ली के विद्यालयों का उद्देश्य भी यही है कि इस भाषा को जीवित, प्रासंगिक और समकालीन बनाए रखा जाए। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के झिरी गांव में तो हिंदू ही नहीं, मुस्लिम परिवार भी संस्कृत में संवाद करते हैं, यहां की दीवारें संस्कृत श्लोकों से सजी हुई हैं और विवाह के गीत तक संस्कृत में गाए जाते हैं। ओडिशा का सासन गांव, जहां केवल 300 की आबादी है, वहां भी हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का गनोड़ा गांव तथा मध्यप्रदेश का बघुवार गांव भी इसी श्रृंखला में आते हैं, जहां संस्कृत भाषा बच्चों के माध्यम से पुनर्जीवित हो रही है।

भारत के बाहर भी संस्कृत के प्रति जिज्ञासा और श्रद्धा निरंतर बढ़ रही है। जर्मनी के 14 से अधिक विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शिकागो, टोक्यो और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संस्कृत साहित्य, व्याकरण, भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्रों के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। वर्ष 2024 में आईसीसीआर (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) द्वारा 45 देशों में आयोजित संस्कृत कार्यक्रमों में हजारों प्रतिभागियों की सहभागिता ने यह सिद्ध किया कि विश्व मंच पर भी इस भाषा की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। हालांकि यह भी सत्य है कि आज व्यवहारिक दृष्टि से संस्कृत का उपयोग सीमित हो चुका है लेकिन डिजिटल युग ने इसके पुनर्जीवन की संभावना को और सशक्त बनाया है। 2024 में जारी नई डिजिटल शिक्षा नीति में संस्कृत को प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक भाषा के रूप में अनिवार्य करने की अनुशंसा की गई। कई राज्यों में ऑनलाइन संस्कृत कोर्स, मोबाइल ऐप्स, संस्कृत संवाद कार्यशालाएं, श्लोक प्रतियोगिताएं और संस्कृत नाट्य मंचन जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। संस्कृत भारती के कार्यक्रमों जैसे 'संवादशाला' और 'बोलचाल संस्कृत' ने लाखों लोगों को सरल संस्कृत में संवाद करना सिखाया है।

तकनीक के क्षेत्र में भी संस्कृत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एआई और एनएलपी (प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण) जैसी उन्नत तकनीकों में संस्कृत की स्पष्टता और व्याकरणिक शुद्धता इसे अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है। आईआईटी मुंबई, आईआईआईटी हैदराबाद और बीएचयू जैसे संस्थान संस्कृत आधारित कंप्यूटेशनल प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं। संस्कृत में केवल धार्मिक या दार्शनिक साहित्य ही नहीं, चिकित्सा, वनस्पति, गणित, खगोलशास्त्र, सैन्यशास्त्र और धातुकर्म जैसे विषयों पर भी विस्तृत ग्रंथ उपलब्ध हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आज भी आयुर्वेद की आधारशिला हैं। आर्यभट्टीय, ब्रह्मस्फुटसिद्धांत और लीलावती जैसे ग्रंथ आधुनिक गणित और खगोलविज्ञान की नींव हैं। नासा और अन्य वैश्विक संस्थाएं संस्कृत ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक ज्ञान को नए संदर्भों में समझने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

आज जब मानवता जलवायु संकट, सांस्कृतिक विघटन, युद्ध और मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही है, संस्कृत हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' और 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' जैसे सार्वभौमिक और समन्वयकारी विचार देती है। यह भाषा केवल शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि जीवन-दर्शन, नैतिकता और करुणा का सजीव मार्ग है। संस्कृत साहित्य में गीता, रामायण, महाभारत, हितोपदेश, पंचतंत्र, नीतिशतक जैसे ग्रंथ आज भी जीवन को दिशा देने वाले प्रेरक स्रोत हैं। हालांकि यह संतोष का विषय है कि संस्कृत को पुन: जीवंत करने के लिए प्रयास हो रहे हैं और पुनरुद्धार की संभावना इसमें सबसे अधिक है। हालांकि यह चेतावनी भी आवश्यक है कि यदि आज हम जागरूक नहीं हुए तो कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भाषा केवल संग्रहीत स्मृति बनकर न रह जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संस्कृत को केवल उत्सवों तक सीमित न रखें बल्कि इसे जीवन में उतारें। यदि हम संस्कृत को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाना चाहते हैं तो हमें इसे केवल स्मृति में नहीं, आचरण में उतारना होगा, तभी यह दिव्य भाषा पुन: भारत की आत्मा बनकर केवल इस देश में नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ बन सकेगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सम्पर्क: 114, गली नं. 6, गोपाल नगर, एम.डी. मार्ग, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043.
---

भारत-अमेरिका दोस्ती की गर्माहट, एच-1बी का झटका: भारतीय प्रतिभा पर 99 लाख का वीज़ा बम -विश्व मंच पर भारत की निर्णायक कूटनीतिक अग्निपरीक्षा!

---

त्योहारों से पहले फीकी पड़ी चीनी की मिठास

-- नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'
स्वतंत्र टिप्पणीकार

त्योहारों की दस्तक के साथ ही रसोई की मिठास पर महंगाई का ग्रहण लग गया है। चीनी की कीमतों में आया उछाल केवल बाजार का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि नीति, मौसम और वैश्विक हालात के जटिल गठजोड़ का परिणाम है। गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों की दस्तक के साथ ही देशभर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। मिल स्तर पर दाम लगभग साढ़े पाँच हजार रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुँच गए हैं, जबकि खुदरा बाजार में पिछले साल की तुलना में करीब तेरह फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल यह है कि आखिर वह कौन-सी वजहें हैं जिनके चलते इस बार त्योहारों से पहले ही चीनी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी है और क्यों सरकार को आयात तक का रास्ता तलाशना पड़ रहा है।

इस संकट की जड़ में सबसे बड़ा कारण गन्ने की फसल का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ा जाना बताया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है, जिसके तहत गन्ने के रस, सिरप और मोलासेस से बड़े पैमाने पर एथेनॉल तैयार किया जा रहा है। इस मौजूदा सीजन में गन्ने से जितनी चीनी बननी थी, उसमें से एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल संयंत्रों में चला गया, जिससे बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा घट गई। विपक्षी दलों का आरोप है कि यही एथेनॉल नीति चीनी की मौजूदा किल्लत और महंगाई की असली वजह है, जबकि सरकार का कहना है कि संकट के पीछे केवल एथेनॉल डायवर्जन नहीं बल्कि कई और कारक भी जिम्मेदार हैं। इन अतिरिक्त कारकों में सबसे अहम है मौसम की मार। पिछले साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की देरी से वापसी के चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में फसल को भारी नुकसान पहुँचा। अत्यधिक बारिश और उसके बाद जलभराव वाले खेतों में धूप और हवा की कमी के कारण गन्ने की बढ़वार प्रभावित हुई। नतीजा यह हुआ कि पहले जो अनुमान लगाए गए थे, उत्पादन उनसे काफी कम रहा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य में भी हालात कुछ बेहतर नहीं रहे और वहाँ भी उत्पादन पूर्व अनुमानों से पीछे छूट गया। इस तरह प्राकृतिक आपदा और नीतिगत फैसले दोनों मिलकर चीनी की उपलब्धता कम करने में भूमिका निभा रहे हैं।

आंकड़ों को देखें तो चालू सीजन के शुरुआती अनुमान में गन्ना उत्पादक राज्यों ने करीब 343 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा था। लेकिन इसमें से करीब चौंतीस लाख टन गन्ना एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने का अनुमान लगाया गया, जिससे शुद्ध चीनी उत्पादन घटकर करीब तीन सौ नौ लाख टन रह गया। बाद में उद्योग जगत के ताजा आकलन में यह आंकड़ा और नीचे खिसकता नजर आया, जिसमें एथेनॉल की ओर मुड़ने वाली मात्रा तीस लाख टन के आसपास आँकी गई और शुद्ध उत्पादन लगभग दो सौ उन्यासी लाख टन तक सिमट गया। जाहिर है, मांग और आपूर्ति के इस अंतर ने बाजार में दाम बढ़ने की जमीन तैयार कर दी। यह संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला देश ब्राजील भी इसी तरह की चुनौती से जूझ रहा है। वहाँ भी सरकार और उद्योग गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ रहे हैं, जिससे चीनी उत्पादन में करीब तीन फीसद तक की कमी आने की आशंका जताई जा रही है। यह गिरावट लाखों टन में आँकी जा रही है। ब्राजील के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में देर से हुई बरसात और तापमान में असामान्य बढ़ोतरी ने भी गन्ने की उपज पर बुरा असर डाला है। चूँकि ब्राजील वैश्विक चीनी बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, इसलिए वहाँ की सप्लाई घटने का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर भी पड़ रहा है।

इसी वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत सरकार कच्ची चीनी के आयात पर विचार कर रही है, ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बहाल की जा सके और त्योहारी मांग के दौरान कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही यह संभावना भी जताई जा रही है कि आगामी 2026-27 सीजन में सरकार चीनी मिलों को गन्ने के रस और बी-हैवी मोलासेस से सीधे एथेनॉल न बनाने का निर्देश दे सकती है, ताकि पहले घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो और उसके बाद ही एथेनॉल उत्पादन को प्राथमिकता दी जाए। यह कदम अगर लागू होता है तो आने वाले समय में चीनी उत्पादन में सुधार की उम्मीद बढ़ सकती है, हालांकि इससे एथेनॉल मिश्रण के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर असर पड़ना भी लाजिमी है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि गन्ने की घटती उत्पादकता भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि सरकार गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई नई नीति लाना चाहती है, तो उसका असर आने में भी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि गन्ने की खेती और उसकी उपज बढ़ाने में कई महीनों का समय दरकार होता है। ऐसे में अल्पकाल में समाधान आयात और भंडार प्रबंधन जैसे उपायों से ही निकलने की उम्मीद है। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि कृत्रिम रूप से बाजार में कमी दिखाने और दाम बढ़ाने की प्रवृत्ति भी इस संकट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने में भूमिका निभा रही है, यानी कुछ मिलों द्वारा जानबूझकर भंडार रोके जाने की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी का माहौल बनता दिख रहा है।

इस पूरे प्रकरण में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना जटिल हो सकता है। एक ओर देश पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर उसी गन्ने पर आधारित यह नीति घरेलू रसोई की जरूरतों से टकरा रही है। यही वजह है कि नीति निर्माताओं के सामने चुनौती केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं के संतुलन की भी है, कि किस हद तक गन्ने का इस्तेमाल ईंधन के लिए हो और किस हद तक भोजन के लिए। आने वाले महीनों में चीनी की कीमतें त्योहारी मांग, मानसून की स्थिति, वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और सरकार की एथेनॉल नीति में संभावित बदलावों पर निर्भर करेंगी। आम उपभोक्ता के लिए राहत तभी संभव होगी जब घरेलू उत्पादन में सुधार आए, आयात समय पर हो और नीतिगत स्तर पर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के बीच बेहतर तालमेल बैठाया जाए। तब तक के लिए मिठास की यह महंगाई आम रसोई के बजट को कड़वा अनुभव कराती रहेगी।
---

ऑफलाइन पर पहरा, ऑनलाइन कोचिंग आजाद — क्या कानून काफी है?
ड्ढठ्ठड्ढश×

ऋह्मञ्जश्वस्ऩ॥च्रस्रूक्छह्मड्ढह्म<ह्लह्लद्बह्यद्धद्बड्डुद्बठ्ठञ्चद्दद्बड्डुद्बद्य.ष्श्वद्ब>
ह्लह्लड्डुष्द्धद्बद्गठ्ठह्लह्य
स्थठ्ठ, ह्वद्द 24, 8:01 ?रू(2 स्रड्ड4ह्य ड्डुद्दश)
ह्लश ड्ढष्: द्वद्ग

ऑफलाइन पर पहरा, ऑनलाइन कोचिंग आजाद — क्या कानून काफी है?

[कोचिंग का इलाज नहीं, शिक्षा की बीमारी का इलाज चाहिए]

[कोचिंग पर कानून का शिकंजा, मगर असली शिकंजा तो परीक्षा का है]

क प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

महाराष्ट्र सरकार ने निजी कोचिंग सेंटर्स के लिए 'महाराष्ट्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2026' का मसौदा पेश किया है। नीट पेपर लीक के बाद सरकार को उस शिक्षा-बाजार की याद आई, जहां बच्चे विद्यार्थी कम, परिणाम पैदा करने वाली मशीन अधिक समझे जाते हैं। मसौदे में फीस, पढ़ाई के घंटे, छात्र सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, विज्ञापन और पंजीकरण पर कड़े प्रावधान हैं। 25 से अधिक विद्यार्थियों वाले केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा और रोजाना पांच घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेंगी। उल्लंघन पर 50 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। कानून का कद बड़ा है; अब देखना है कि उसका हाथ भी उतना ही लंबा है या नहीं।

मसौदे का पहला शिकंजा पंजीकरण है। 25 से अधिक विद्यार्थियों वाले हर कोचिंग केंद्र का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पुराने केंद्रों को छह महीने मिलेंगे, पंजीकरण तीन वर्ष के लिए होगा और हर शाखा अलग केंद्र मानी जाएगी। शिक्षक स्नातक होने चाहिए तथा संज्ञेय अपराध में शामिल लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। रैंक की गारंटी और भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक होगी। यह जरूरी है, क्योंकि अब तक कई संस्थान बिना जवाबदेही शिक्षा बेच रहे थे। मगर असली सवाल पंजीकरण नहीं, निरीक्षण है। निरीक्षक कम और संस्थान हजारों हुए तो कागजों पर सब ठीक, जमीन पर सब पहले जैसा रह सकता है। कानून की स्याही तभी असरदार है, जब निगरानी की आंख खुली रहे।

रोज पांच घंटे की कोचिंग सीमा राहत देती है। सुबह बहुत जल्दी और रात देर तक कक्षाएं नहीं चलेंगी। साप्ताहिक अवकाश होगा और छुट्टी के अगले दिन टेस्ट नहीं लिया जा सकेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट अनिवार्य होंगे। यह जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगिता ने कई किशोरों को किताब से पहले तनाव पढ़ना सिखा दिया है। लेकिन संस्थान में पांच घंटे बंद हुए तो घर में होमवर्क, ऑनलाइन टेस्ट और निजी ट्यूशन के घंटे बढ़ सकते हैं। दबाव का ठिकाना बदलेगा, दबाव खत्म नहीं होगा। ऑफलाइन सीमा से ऑनलाइन कोचिंग और ऐप-आधारित टेस्ट का प्रभाव और बढ़ सकता है। समस्या कोचिंग के समय की नहीं, उस शिक्षा व्यवस्था की है जिसने सफलता को एक परीक्षा तक सीमित कर दिया है।

फीस पर प्रस्तावित नियम अभिभावकों के लिए बड़ी राहत हैं। कोचिंग केंद्र घोषित फीस से अधिक नहीं ले सकेंगे और बीच में शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे। पढ़ाई छोड़ने पर दस दिन में फीस लौटानी होगी, जिसमें हॉस्टल और मेस की रकम भी शामिल होगी। हर भुगतान की रसीद अनिवार्य होगी। यह उस कारोबार पर रोक है, जहां प्रवेश के समय सपने किस्तों में और बाद में अतिरिक्त शुल्क सामने आता है। खतरा है कि बड़े संस्थान नियमों की दरारें खोज लें, जबकि छोटे संस्थान उतने सक्षम नहीं होंगे। मसौदे पर सुझाव मांगे जा रहे हैं और चार सितंबर तक आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। अंतिम कानून में पारदर्शिता के साथ समान प्रवर्तन भी जरूरी है।

सुरक्षा प्रावधान सबसे गंभीर हैं। बेसमेंट में कक्षाओं पर रोक होगी। हर विद्यार्थी के लिए कम-से-कम एक वर्गमीटर जगह जरूरी होगी। अग्नि व भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे। सीसीटीवी फुटेज एक महीने सुरक्षित रखना होगा। पानी, अलग शौचालय, प्राथमिक उपचार और पार्किंग जरूरी होंगे। डमी स्कूल मॉडल पर पाबंदी होगी और नियम तोड़ने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। इन प्रावधानों का महत्व इसलिए है कि हादसे के बाद सुरक्षा का भाषण किसी बच्चे की जान नहीं बचा सकता। मगर पुराने भवनों में अतिरिक्त जगह निकालना आसान नहीं; कई केंद्र बंद हो सकते हैं। इसलिए मानक कठोर हों, पर निरीक्षण निष्पक्ष और व्यावहारिक हो।

महाराष्ट्र के रास्ते पर दूसरे राज्य भी बढ़ रहे हैं। राजस्थान का 2025 का कानून 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले केंद्रों पर लागू है। असम ने 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम मंजूर किए हैं। हरियाणा, बिहार और झारखंड में भी कानून या मसौदे आए हैं। दिल्ली सरकार भी अपनी व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। केंद्र की 2024 की गाइडलाइंस के बाद राज्यों की सक्रियता बढ़ी है। महाराष्ट्र का मसौदा अधिक व्यापक और कठोर है—नियमन 25 विद्यार्थियों से शुरू होता है और जुर्माना 50 लाख तक है। फिर भी पूरे देश में एक कानून बनना आसान नहीं, क्योंकि हर राज्य में राजनीति, प्रशासन और कोचिंग उद्योग का प्रभाव अलग है।

सवाल यह भी है कि सजा कितनी होगी और न्याय कितना। मामूली उल्लंघन पर एक से पांच लाख और गंभीर उल्लंघन पर दस से पचास लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। पंजीकरण रद्द और केंद्र बंद भी कराया जा सकता है। कागज पर व्यवस्था मजबूत है। लेकिन बड़े संस्थान जुर्माने को कारोबार की लागत मानकर भर सकते हैं, जबकि छोटा केंद्र बंद हो सकता है। बंबई हाईकोर्ट ने करीब दो दशक पहले भी इस क्षेत्र के नियमन की जरूरत बताई थी, पर ठोस कानून नहीं बन पाया। नीट लीक ने सरकार को फिर जगाया है। शिकायत तंत्र कमजोर, निरीक्षण सीमित और राजनीतिक प्रभाव मजबूत रहा तो कानून की लाठी गरीब पर भारी और प्रभावशाली पर हल्की पड़ सकती है।

महाराष्ट्र का मसौदा सही दिशा में कदम है, लेकिन इसे शिक्षा का इलाज समझना भूल होगी। कोचिंग उद्योग उस बीमारी का लक्षण है, जिसकी जड़ कमजोर स्कूली शिक्षा, परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था और सफलता की सामाजिक सनक में है। स्कूल बेहतर होंगे तो कोचिंग का साम्राज्य अपने आप छोटा होगा। इसलिए पंजीकरण के साथ ईमानदार निरीक्षण, फीस निगरानी, सुरक्षित भवन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है। केंद्र को राज्यों के अनुभवों से सीखकर राष्ट्रीय ढांचा भी बनाना चाहिए। कानून बनाकर सरकार ने दरवाजा खोला है; अब भीतर जाकर देखना होगा कि पढ़ाई हो रही है या डर की फैक्ट्री चल रही है। वरना यह मसौदा भी कागजी शेर साबित होगा—दहाड़ बड़ी, मगर बच्चे उसी पुराने पिंजरे में।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

शिक्षाविद्

बड़वानी (मप्र)

ईमेल: ह्लह्लद्बह्यद्धद्बड्डुद्बठ्ठञ्चद्दद्बड्डुद्बद्य.ष्श्वद्ब